www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 11 | जौनपुर, सोमवार, 24 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राहुल गांधी नकली गुस्सा दिखाने वाले प्रोफेशनल आंदोलनकारी – तुहिन सिन्हा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए. सिन्हा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली गुस्सा दिखाने वाला प्रोफेशनल आंदोलनकारी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, बेवजह मनुस्मृति को गलत संदर्भ में पेश कर हिंदू मान्यताओं पर हमला करना उनका रोज का काम बन गया है, जबकि महात्मा गांधी ने खुद 1928 में मनुस्मृति की कई बातों को जीवन में अपनाने योग्य बताया था।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए. सिन्हा ने कहा, ष्एक हफ्ते पहले सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के गरीब स्टूडेंट्स को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10–12 सालों में हुए सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल गया कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके तुरंत बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया।ष उन्होंने आगे कहा कि अब स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और उन्हें लगता है कि यह धोखा सीधे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने किया है। गुस्से और नाराजगी में जेएमएम के कार्यकर्ता कथित तौर पर रांची के साथ–साथ कोडरमा और हजारीबाग में भी हर दिन गरीब स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं।राहुल गांधी के मनुस्मृति वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ष्राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत है कि यह देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। इसलिए, किसी न किसी मुद्दे पर बेवजह मनुस्मृति को गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट करना और एक तरह से हिंदू मान्यताओं पर हमला करना राहुल गांधी का रूटीन बन गया है।ष तुहिन सिन्हा ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब संसद में भी छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उस समय एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अचानक आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को श्गोमूत्र एक्सपर्टश कह दिया, तो दूसरी तरफ खड़गे ने उस दिन फिर मनुस्मृति पर हमला किया।उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को यह जानने की जरूरत है।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं समस्याएं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के गुरुदेव नगर हरगांव की रहने वाली पूनम देवी सोमवार को 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री से मिलीं और गोपालन की अभिलाषा बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उनकी मांगों पर विचार करते हुए अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और नियमानुसार योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। वहीं, एक दिव्यांग ने अवैध कब्जे की भी शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच कराकर निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में पूनम देवी ने लिखा कि वह गोपालन करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अभी उनके पास पांच गाय हैं और अन्य गोमाता को रखने के लिए पर्याप्त

जगह भी है। ऐसे में उन्हें और भी गाय दिला दी जाए, जिससे वे दूध आदि की बिक्री कर परिवार को समृद्ध करेंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाए। 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री ने एक–एक कर सभी का हालचाल जाना, फिर सभी की समस्याएं भी पूछीं। पूनम का प्रार्थना पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री ने उनकी हौसलाअफजाई भी की। मुख्यमंत्री ने पूनम से कहा कि हम आपको सरकार की तरफ से नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। आप गोसेवा कीजिए क्योंकि गोमाता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने उनसे अनुभव साझा किया कि आप मन से गोसेवा करो, सारी बाधाएं और कष्ट दूर होंगे। पूनम ने भी श्रावण मास में इच्छा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारत–न्यूजीलैंड में नई साझेदारी, वेलिंगटन में रक्षा वार्ता के दौरान लिया गया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। यह वार्ता भारत के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव रिचर्ड शिमट की सह–अध्यक्षता में संपन्न हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना और श्रोडमैप 2030श के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। भारत और न्यूजीलैंड द्वारा वेलिंगटन में दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता शुरू की है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह रक्षा रणनीतिक वार्ता हो रही है। दोनों पक्षों ने इस बातचीत में रोडमैप 2030 के तय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग को और व्यापक बनाने पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई इस वार्ता की सह–अध्यक्षता भारत के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप

सचिव रिचर्ड शिमट ने की। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही दोनों पक्षों ने रोडमैप 2030 के तय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग को और व्यापक बनाने पर चर्चा की। बता दें भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को अहम मानते हैं। ऐसे में रणनीतिक बातचीत में समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा से जुड़े सहयोग को मजबूत करने से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे सीएम मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक गरज–चमक, बिजली गिरने, भारी से बहुत भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र, भोपाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। यह चेतावनी 26 अगस्त तक के लिए

जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और मध्य मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है।23 अगस्त की सुबह 8रू30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। गोहपाल क्षेत्र में 98 मिमी, जैतहरी में 85.6 मिमी, बुढार में 85 मिमी और बैहर में 82 मिमी बारिश हुई। शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और सतना जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। टीकमगढ़ में 39 किमी प्रतिघंटा और होशंगाबाद में 35 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, डिंडोरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह और सागर जिलों में अलग–अलग दिनों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ गरज–चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है।

बंबीहा गैंग के तीन कुख्यात आरोपी भारत पहुंचे, अब तक 51 अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय एजेंसियों ने मलेशिया में कार्रवाई करते हुए तीन फरार भारतीय गैंगस्टरों को पकड़ा है। उन्हें भारत वापस लाकर पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है। तीनों आरोपी कथित तौर पर बंबीहा गैंग से जुड़े हैं और उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के 'सुरक्षित भारत' के विजन के तहत भारतीय एजेंसियां विदेशों में छिपे कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स

पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि भारतीय एजेंसियों ने मलेशिया में तीन फरार भारतीय गैंगस्टरों को पकड़ा, उन्हें भारत वापस भेजा और पुलिस कस्टडी में सौंप दिया। ये फरार अपराधी जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह हैं जो कि बंबीहा गैंग से जुड़े हैं और उन पर कई अपराधों के आरोप हैं। इनमें जबरन वसूली, सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम कोशिश शामिल है। पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के विजन के तहत, हमारी एजेंसियों ने अकेले 2026 में 51 कुख्यात अपराधियों को वापस लाने में मदद की है। इसी मामले में 19 अगस्त को पंजाब डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। भगोड़े चाहे कहीं भी छिपे हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और कानून के दायरे में लाएंगे। इन आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ बहबल के रूप में हुई है। यह फरीदकोट का रहने वाला है।

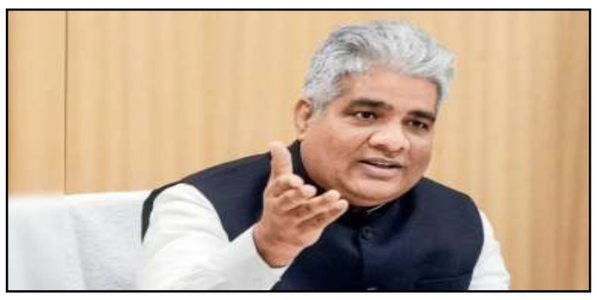

भारत ने 2011-2020 के दौरान 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाल की - भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भूमि बहाली भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता है और यह सतत भूमि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई तथा ग्रामीण विकास के प्रयासों का अभिन्न हिस्सा है। मंगोलिया के उलानबटार में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के 17वें सम्मेलन द्वारा आयोजित एक साइड इवेंट को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि भारत भूमि बहाली को किसी एक कार्यक्रम तक सीमित हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि टिकाऊ और लचीले विकास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है। मंत्री ने बताया कि भारत बॉन चौलेंज के प्रमुख वैश्विक प्रतिबद्धता वाले देशों में शामिल है। भारत ने 2015 में क्षरित और वनों से वंचित भूमि को बहाल करने की प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2030

तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर कर दिया गया भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने हाल ही में बॉन चौलेंज पर अपनी दूसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2011 से 2020 की अवधि को शामिल किया गया है। इस दौरान देश में 21.76 मिलियन हेक्टेयर (2.176 करोड़ हेक्टेयर) भूमि को बहाली के दायरे में लाया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रयास से लगभग 1.22 अरब मानव–दिवस रोजगार भी सृजित हुआ। इससे पता चलता है कि भूमि बहाली न केवल पर्यावरणीय लाभ देती है, बल्कि रोजगार पैदा करने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि आकलन केवल बहाल की गई भूमि के क्षेत्रफल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वन, कृषि, मृदा एवं जल संरक्षण तथा अन्य भूमि उपयोग प्रणालियों में किए गए बहाली कार्यों को भी शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि पिछली रिपोर्टिंग प्रक्रिया ने भूमि बहाली के परिणामों, वित्तीय प्रवाह और आजीविका पर प्रभाव की निगरानी प्रणालियों को और मजबूत करने की आवश्यकता को सामने रखा है। इसी दिशा में भारत 2021–2025 की अवधि के लिए अगली रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर काम कर रहा है। यह कार्य सतत भूमि प्रबंधन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और के सहयोग से किया जा रहा है।

अपने स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को अपने पुराने विद्यालय कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज पहुंचे तो बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। कभी इसी विद्यालय में विद्यार्थी बनकर पढ़ाई करने वाले ज्ञानेश कुमार इस बार शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उन्हें लोकतंत्र, चुनाव, मताधिकार तथा जिम्मेदार नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया। अपने छात्र जीवन की यादों को साझा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कॉलेज ने उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, चुनौतियों से लड़ने का साहस और सही विचारों को आत्मसात करने की क्षमता भी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल और कॉलेज का समय जीवन का ऐसा दौर होता है, जब अच्छे शिक्षक, वातावरण और अनुभव व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षकों ने उन्हें बहुत कुछ दिया और विद्यालय से मिली सीख आगे चलकर उनके जीवन में बेहद काम आई। विद्यार्थियों से संवाद

के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें अपने विद्यालय से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, उसी तरह आज के विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षकों और विद्यालय के वातावरण से मिलने वाली सीख को ग्रहण करना चाहिए। निर्माण में भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है। जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने मताधिकार के साथ–साथ उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता बनने की पात्रता, मतदान और निष्पक्ष चुनाव से जुड़े कई सवाल पूछे।

हरियाणा में गोदरेज समूह करेगा 20,000 करोड़ रुपये का निवेश, 40,000 रोजगार के अवसर

हरियाणा, (एजेंसी)। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत समूह राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि प्रस्तावित निवेश से करीब 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। यह निवेश योजना हरियाणा में समूह की मौजूदा मौजूदगी को और मजबूत करेगी। समूह अब तक राज्य में करीब 12,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है और उसके विभिन्न कारोबारों में लगभग 9,000 लोग कार्यरत हैं। समूह ने कहा कि प्रस्तावित निवेश हरियाणा की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता तथा बढ़ते वाणिज्यिक और शहरी विकास

के अवसरों में उसके भरोसे को दर्शाता है। नियोजित निवेश में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। रियल एस्टेट कारोबार ने हरियाणा में पहले ही करीब 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और वित्त वर्ष 2028 तक 16,000 करोड़ रुपये और निवेश करने की योजना है। कंपनी के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत और कुरुक्षेत्र में 18 प्रोजेक्ट हैं। भविष्य की परियोजनाओं से 11,000 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। समूह के रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी कारोबार गोदरेज वेंचर्स की गुरुग्राम में ळतंकम ्र कार्यालय बुनियादी ढांचे में 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना है। प्रस्तावित निवेश से 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इससे गुरुग्राम के वाणिज्यिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों के लिए शहर की आकर्षक क्षमता बढ़ेगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के चेयरपर्सन पीरोजशा गोदरेज ने कहा कि हरियाणा समूह के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

सड़क हादसों व गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के लिए 'संजीवनी' साबित हो रही एएलएस एम्बुलेंस सेवा – सुमन समीर द्विवेदी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। सड़क हादसों मे गंभीर रुप से घायल तथा गंभीर रुप से पीडित मरीजों को तत्काल हायर सेंटर अस्पताल पहुंचाने में एएलएस एंबुलेंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।यह जानकारी कंपनी के सहायक प्रबंधक सुमन समीर द्विवेदी ने दिया।बताया कि एएलएस एम्बुलेंस चलता फिरता एक मिनी आईसीयू है।इस एएलएस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, सिरिंज पंप, मल्टीपैरा मॉनिटर और एईडी मशीन आदि उपकरण मौजूद हैं।जब किसी मरीज को छोटे अस्पताल से विभिन्न हायर सेंटर पर इलाज के लिए रेफर किया जाता है, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस एंबुलेंस का उपयोग किया जाता है।बताया कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में एएलएस एंबुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। अयोध्या जिले मे 294,बस्ती में 201,अंबेडकरनगर में 232 तथा संतकबीर नगर में 349 एएलएस एंबुलेंस के संचालन हो रहा है।बताया कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल मरीजों को ही अस्पताल पहुंचाने ही नही बल्कि रास्ते में मरीज की स्थिति पर नजर बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध कराना भी इस सेवा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है।बताया कि आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का हर मिनट महत्वपूर्ण होता है।ऐसे में इस एंबुलेंस में तैनात ईएमटी और पायलट आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं।ईएमटी मरीज की चिकित्सकीय जरूरतों पर नजर रखता है,जबकि पायलट सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से मरीज को निर्धारित हायर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का कार्य रहता है।बताया कि सड़क हादसों मे अक्सर मरीजों की स्थिति गंभीर होती है।ऐसे समय में एंबुलेंस टीम का त्वरित रिस्पांस और बेहतर समन्वय बेहद अहम हो जाता है।बताया कि इस एंबुलेंस सेवा का मुख्य उद्देश्य केवल गंभीर रुप से घायल व अन्य गंभीर बीमारियों से घर से ग्रसित मरीजों को अस्पताल पहुंचाना ही नहीं,बल्कि अस्पताल पहुंचने तक उसे आवश्यक चिकित्सकीय सपोर्ट उपलब्ध कराना है।उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशिक्षित ईएमटी मरीज की

स्थिति के अनुसार आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और पूरी टीम का लक्ष्य मरीज को सुरक्षित एवं जल्द से जल्द उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाना प्रथम प्राथमिकता होती है।

संपादकीय

विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय पहले यह कह चुका है कि जंतर–मंतर पर शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विरोध प्रदर्शन संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब इस पैमाने को नहीं बदला जाना चाहिए। यह निराशाजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर–मंतर से हटा कर प्राथमिक प्रतिरोध स्थल को रामलीला मैदान तय करने की याचिका को गंभीरता से लिया। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन पर पहले ही कई बंदिशें लग चुकी हैं। ऐसे में आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसी याचिका को अहमियत देने को सरकार एक अवसर के रूप में ले सकती है। इस हफ्ते एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला मैदान को प्राथमिक प्रदर्शन स्थल बनाया जाए। कोर्ट ने इसे ष्महत्वपूर्ण मामलाष मानते हुए सॉलीसिटर जनरल को केंद्र से इस पर सलाह लेने का निर्देश दिया। यहां यह याद करना उचित होगा कि तीन दशक पहले विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक स्थल बोट क्लब था, जो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने है। विरोध के स्वर के प्रति असहनशीलता दिखाते हुए तत्कालीन सत्ताधारियों ने प्राथमिक प्रदर्शन स्थल को जंतर–मंतर तय कर दिया। दिल्ली पुलिस के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी प्रदर्शन में 1,000 से कम लोग शामिल होने हों, तो जंतर–मंतर पर आयोजन की अनुमति दी जाती है। 1,000 से अधिक संभावित उपस्थिति के लिए रामलीला मैदान तय किया गया है। अभी हाल में जंतर–मंतर पर हुए श्कॉकरोच्च प्रदर्शन से सरकार के लिए कठिन स्थितियां पैदा हुईं। जंतर–मंतर से भी दूरी कम है, इसलिए वहां से संसद मार्च आयोजित करना आसान रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को इसी पृष्ठभूमि देखा जाना चाहिए। इस सिलसिले में खुद सर्वोच्च न्यायालय के 2018 में दिए एक निर्णय को याद करना उचित होगा, जब कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान शिफ्ट करने के एक आदेश को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जंतर–मंतर या बॉट क्लब जैसी जगहों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विरोध प्रदर्शन संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब इस पैमाने को नहीं बदला जाना चाहिए। लोगों की आवाज संसद और सरकार तक पहुंच सके, इसके लिए निकटतम जगह पर प्रदर्शन के जन अधिकार की रक्षा अति अवश्यक है।

सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति

भविष्य को सशक्त बनाना

चिप्स से एआई तकरू भारत की टेक्नोलॉजी लीडरशिप का निर्माण

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की आधारशिला हैं। स्मार्टफोन, वाहन, उपग्रह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों से लेकर आधुनिक औद्योगिक उपकरणों तक लगभग हर क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विस्तार के कारण उन्नत चिप, विशेष प्रोसेसर और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक–दूसरे से गहराई से जुड़ गए हैं। भारत इसी बदलते तकनीकी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चिप डिजाइन और विनिर्माण से लेकर उन्नत पैकेजिंग, कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे और स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तक अपनी क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार की विभिन्न पहलों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को जोड़ते हुए ऐसा एकीकृत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब ये क्षमताएं वैश्विक तकनीकी नेतृत्व और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। भारत सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताएं विकसित कर रहा है। इसमें चिप डिजाइन, विनिर्माण, उन्नत पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण और आवश्यक सामग्री से लेकर कुशल मानव संसाधन तैयार करना शामिल है। घरेलू क्षमता मजबूत होने से भारत भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और विनिर्माण में अधिक सक्षम हो रहा है। भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सेमीकॉन 1.0 के तहत 76 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ आधार तैयार किया गया। इसके अंतर्गत चिप डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण, सामग्री और कुशल प्रतिभाओं सहित पूरी मूल्य श्रृंखला को समर्थन दिया गया। अब सेमीकॉन 2.0 इस आधार को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। जुलाई 2026 में इसके लिए 1 लाख 27 हजार 500 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। सेमीकॉन इंडिया 2.0 छह रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें चिप डिजाइन, मशीन और सामग्री, सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र, उन्नत परीक्षण एवं पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास शामिल हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने और भारत को भविष्य के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। भारत में छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र, डिस्प्ले निर्माण तथा उन्नत पैकेजिंग सुविधाएं शामिल हैं। इनमें से तीन सुविधाओं में वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। यह भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के नीति निर्माण से आगे बढ़कर वास्तविक विनिर्माण की दिशा में पहुंचने का संकेत है। इन सुविधाओं से वाहन उद्योग, दूरसंचार, अंतरिक्ष एवं विमानन, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र कच्चे सिलिकॉन वेफर को कार्यशील एकीकृत परिपथ और सूक्ष्मचिप में बदलते हैं। डिस्प्ले निर्माण संयंत्र मोबाइल फोन, कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सपाट तथा लचीली स्क्रीन तैयार करते हैं। वहीं उन्नत पैकेजिंग तकनीक संवेदनशील चिप को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनका प्रदर्शन और उपयोग अवधि बेहतर होती है। भविष्य की कार्यबल जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने चिप्स टू स्टार्ट–अप जैसी पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर कौशल विकास पर जोर दिया है। इसके तहत 320 शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और 68 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्नत चिप डिजाइन क्षमता तक पहुंच मिल रही है। डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त 105 स्टार्ट–अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन उपकरणों के लिए सहायता प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन उपकरण ऐसे सॉफ्टवेयर मंच हैं, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन, अनुकरण, सत्यापन और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इनके माध्यम से निर्माण से पहले संभावित त्रुटियों का पता लगाया जाता है और चिप की कार्यक्षमता, ऊर्जा दक्षता तथा विश्वसनीयता को बेहतर किया जाता है। अप्रैल 2026 तक 75 संस्थानों द्वारा 211 चिप डिजाइन का अंतिम डिजाइन चरण पूरा किया जा चुका था। इनमें से सात चिप का अलग–अलग तकनीकी स्तरों पर सफल निर्माण भी किया गया है, जिसमें 12 नैनोमीटर जैसे उन्नत स्तर शामिल हैं।

भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि पर बिहार से उठ रहे सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना ही होगा

नीरज

1996 की भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है, ऐसे में ढाका नई संधि की मांग तेज कर रहा है और सूखे के मौसम में न्यूनतम जल प्रवाह की गारंटी जैसी शर्त जोड़ना चाहता है, मगर केंद्र और बिहार में सत्तारुढ़ एनडीए के एक प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने लेख के माध्यम से जो सवाल उठाए हैं, उसने पूरे मामले का नया मोड़ दे दिया है। उनका संदेश साफ है कि भारत को केवल बांग्लादेश के साथ नई संधि पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले यह तय करना होगा कि बदलती जलवायु, घटते प्रवाह और बढ़ती जरूरतों के बीच गंगा का पानी भारत के अपने राज्यों खासकर बिहार के बीच किस आधार पर बांटा जाएगा। यही वह सवाल है जो 2026 के बाद गंगा की राजनीति को केवल जल बंटवारे का मुद्दा नहीं रहने देता, बल्कि इसे राष्ट्रीय हित, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीति और सामरिक रणनीति के केंद्र में ला खड़ा करता है। दरअसल, ढाका चाहता है कि नई संधि में एक 'गारंटी क्लॉज' शामिल हो, जिसके तहत सूखे के मौसम में बांग्लादेश को गंगा के पानी की एक न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित की जाए। 1977 के समझौते में इस तरह की गारंटी का प्रावधान था, लेकिन 1996 की संधि में इसे शामिल नहीं किया गया। बांग्लादेश का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित होते सूखे मौसम के प्रवाह और पानी की घटती उपलब्धता के कारण पुराना फार्मूला अब उसकी जरूरतों और वर्तमान परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करता। लेकिन ठीक यही तर्क भारत, विशेषकर बिहार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संजय झा का सवाल है कि तीन दशक पुरानी गणना के आधार पर भारत खुद को एक और लंबे अंतरराष्ट्रीय दायित्व में क्यों बांधे? गंगा का अविरल प्रवाह बिहार में कई हिस्सों में टूट रहा है, नदी के चौनल बदल रहे हैं, कई इलाकों में भूजल संकट गहरा रहा है और दूसरी ओर दक्षिण बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के साथ–साथ उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके भी पानी की असमानता से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब नदी का व्यवहार ही बदल चुका है तो 1996 के आंकड़ों और फार्मूले को भविष्य के लिए स्थायी मान लेना बिहार के हितों पर भारी पड़ सकता है। देखा जाये तो फरक्का पर विवाद इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील केंद्र है। बांग्लादेश लंबे समय से फरक्का बैराज को सूखे मौसम में उसके हिस्से के जल प्रवाह में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। वहां की ओर से इसे लेकर तीखी भाषा भी इस्तेमाल की गई है। भारत का पक्ष अलग है। भारत फरक्का को बांध नहीं बल्कि एक डायवर्जन संरचना मानता है, जिसका उद्देश्य गंगा के पानी का एक हिस्सा हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ना है, जबकि शेष प्रवाह बांग्लादेश की दिशा में आगे बढ़ता है। भारत यह भी कहता रहा है कि जल प्रवाह से जुड़ा डेटा संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से साझा किया जाता है। लेकिन अब असली सवाल केवल फरक्का नहीं है। सवाल यह है कि गंगा पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता तय करने से पहले भारत के भीतर गंगा बेसिन वाले राज्यों यानि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारों और जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन क्यों नहीं होना चाहिए? यही वह बिंदु है जहां संजय झा की मांग बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार की आबादी 1996 के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। पीने के पानी, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों का दबाव भी कई गुना बढ़ा है। राज्य को यदि अपनी कृषि, सिंचाई परियोजनाओं और जल प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है तो उसे पहले से यह पता होना चाहिए कि गंगा बेसिन में उसका वास्तविक और न्यायसंगत हिस्सा कितना है। नई संधि से पहले भारत के भीतर वैज्ञानिक जल आवंटन बिहार के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ हो सकता है। भारत के लिए भी यह केवल बिहार बनाम बांग्लादेश का प्रश्न नहीं है। गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच साझा 54 प्रमुख नदियों वाले व्यापक जल संबंधों का हिस्सा है। यदि भारत बिना घरेलू जल संतुलन तय किए बांग्लादेश को न्यूनतम प्रवाह की गारंटी देता है, तो भविष्य में सूखे के गंभीर वर्षों में अपने राज्यों की जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच टकराव पैदा हो सकता है। इसलिए नई संधि का आधार 1950 के दशक या 1990 के दशक के आंकड़े नहीं, बल्कि वर्तमान हाइड्रोलॉजिकल डेटा, जलवायु अनुमान, वास्तविक प्रवाह और समय–समय पर समीक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। भारत की संसदीय समिति भी इस दिशा में संकेत दे चुकी है कि संधि के नवीनीकरण पर बातचीत में बिहार और पश्चिम बंगाल की चिंताओं, अपडेटेड जल आंकड़ों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाना चाहिए। इसका अर्थ साफ है कि नई व्यवस्था यदि बनती है तो वह पुराने अंकगणित की कॉपी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ, मान लीजिये कि अगर संधि समाप्त हो जाती है और नई संधि नहीं हो पाती तब

क्या होगा? ऐसे में संभव है कि बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर सकता है। ढाका संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जल अधिकार और सूखे के मौसम में जल संकट का सवाल उठा सकता है। इससे भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया तनाव पैदा हो सकता है। बांग्लादेश घरेलू राजनीति में भी गंगा जल को एक संवेदनशील राष्ट्रवादी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में भारत पर इसका असर केवल कूटनीतिक छवि तक सीमित नहीं रहेगा। जल विवाद सीमा पार सहयोग, नदी प्रबंधन, व्यापार और व्यापक भारत–बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि नई दिल्ली के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता न तो आंख बंद करके पुरानी संधि का नवीनीकरण है और न ही जल प्रश्न को अनिश्चितता में छोड़ देना। भारत को इस मौके का इस्तेमाल एक मजबूत, आधुनिक और संतुलित जल रणनीति बनाने में करना चाहिए। पहले अपने राज्यों के हितों का वैज्ञानिक निर्धारण, फिर बांग्लादेश के साथ पारदर्शी बातचीत। नई संधि में वास्तविक प्रवाह के आधार पर आवंटन, छोटे समीक्षा चक्र, जलवायु परिवर्तन के अनुसार संशोधन और असाधारण परिस्थितियों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जा सकते हैं। बहरहाल, दिसंबर 2026 की समयसीमा इसलिए केवल एक संधि की समाप्ति नहीं है। यह भारत के सामने अपनी गंगा नीति को नए सिरे से लिखने का अवसर है।

वंदे मातरम के अपमान से कांग्रेस के तुष्टिकरण की पोल खुली

प्रवीण

मातृभूमि के स्तुति गीत को आधा स्वीकारना और आधा त्यागना, यह किस प्रकार की संतान की भक्ति है? भद्र बंगाल की सौ वर्षों की व्यथा, वेदना ही इस लोकोक्ति रूप में प्रकट हुई है। भारतीय स्वतंत्रता–संग्राम का शायद ही कोई दूसरा गीत "वन्दे मातरम" जितना

भावात्मक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रहा हो। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी की यह रचना केवल साहित्य नहीं अपितु वह स्वदेशी आन्दोलन, क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय जागरण का उद्भट उद्घोष बनी थी। 15 अगस्त, 2026 को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में कारित घृणित कृत्य से कांग्रेस का इस्लामिक डीएनए पुनः सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम् के इस अपमान के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दशक भर कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उपस्थित थे। दुस्साहस और दुर्भाग्य का विषय यह है कि इन तीनों ने ही वंदे मातरम् के अपमान के इस दुष्कृत्य को प्रारंभ किया था। इस दुर्भाग्यजनक घटना के बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने देश को स्पष्टीकरण देना प्रारंभ किया कि – "सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् का अपमान नहीं किया बल्कि वे बुजुर्ग खड़गे जी को खड़े होने के कारण असहज होता देखकर उनके लिए कुर्सी मंगा रही थी"। यहीं से कांग्रेस नेतृत्व की मूढ़ता, राष्ट्र अनास्था व मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्ष में दुराग्रह रखने के चरित्र की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है। इस घटनाक्रम के अंतरतत्व को समझिए। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व द्वारा 'वंदे मातरम्' का यह अपमान बुरा लगा इसलिए ही उन्होंने बिना केंद्र या प्रदेश नेतृत्व के कहे ही इस घटना पर कांग्रेस नेतृत्व का बचाव प्रारंभ कर दिया था। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट डाली और कांग्रेस नेतृत्व का बचाव किया। यह 'वंदे मातरम्' और 'मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेसी प्रवृत्ति' के विरोध का प्रतीक था। इस मनोभाव को कांग्रेस के इटालियन नेतृत्व ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस ने इस घटना पर अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं होती। कांग्रेस ने तो अपनी हठधर्मिता, अड़ियलपन, मति मूढ़ता की हद तो तब दिखा दी जब उसने अपनी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी में 'वंदे मातरम्' को पूर्ण रूप में नहीं गाने के लिए प्रस्ताव ही पारित कर दिया। 'वंदे मातरम के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तव्य जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है। गांधी जी तो इस बात के पक्षधर थे कि यह गीत संपूर्ण देश को जोड़ने वाला प्राणतत्त्व है और इसे इसके पूर्ण वैभव के साथ संपूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी जी ने इसके समर्थन में अपनी स्पष्ट राय रखी थी, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टिकरण की अपनी राजनैतिक कुटिलताओं और प्राथमिकताओं के चलते गांधी जी की एक न चलने दी। इतिहास यह भी है कि, यह दुखद एतिहासिक पृष्ठ रहस्यमयी भी है। रहस्य यह कि – "अंततः वह कौन सी कमजोरनस थी,, जिसके आधार पर नेहरू जी ऐसे निर्णय भी गांधी जी से करवा लेते थे जिनके लिए गांधी जी कभी भी तैयार नहीं थे"। गांधी जी वंदेमातरम् विभाजन हेतु असहमत थे। गांधी जी बंग–भंग हेतु भी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने कहा था कि "इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा"। गांधी जी स्वतंत्रता पश्चात् कांग्रेस को विसर्जित करने हेतु भी संकल्पित थे। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता पश्चात् हम एक बूँद की स्याही लेंगे और यह लिख देंगे – "इस देश में गौहत्या वैसा ही दंड होगा जैसा मानव हत्या के लिए होता है"। स्वच्छता, हिंदी राष्ट्रभाषा, ग्रामवासी भारत आदि हेतु भी गांधी जी प्रतिबद्ध थे। कांग्रेस ने सात दशकों की सत्ता में इन विषयों को त्याज्य रखा। 'भारत में रामराज स्थापना' को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था किंतु 'नेहरू–गांधी कांग्रेस' मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए श्रीराम को ही कल्पना सिद्ध करने के प्रयास में लग गई। कांग्रेस स्वयं को सेकुलर सिद्ध करने के अनथक प्रयास करने लगी थी और 'रामेश्वरम् रामसेतु' के विध्वंस, विनाश, भंजन, खंडन हेतु मशीनें समुद्रतट पर भेज चुकी थी। 'मुस्लिम तुष्टिकरण' हेतु कांग्रेस ने न जाने कितने ही कांड इस देश में किया और सतत–निरंतर किए हैं। आश्चर्य और दुस्साहस का विषय यह है कि 'मुस्लिम तुष्टिकरण' के लिए देश भर से लताड़े जाने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व इस बात को समझ ही नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता इस बात कोई समझ भी रहा है और वह कांग्रेस की 'मुस्लिम तुष्टिकरण' की नीति के विरोध में भी है, तब ही तो 'कार्यकर्ता बेचारे' ने सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में आकर यह कहा था कि "सोनिया जी वंदे मातरम् का गान रोक नहीं रही थी बल्कि खड़गे जी के लिए कुर्सी बुला रही थी"। 'वंदे मातरम और 'मुस्लिम तुष्टिकरण' की यह कांग्रेस कार्यकर्ता की नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार करना चाहिए थे किंतु कांग्रेस ने 'राम पथ' को नहीं बल्कि 'रोम पथ' को चुना हुआ है। 26 अक्टूबर– 1 नवम्बर 1937 की कलकत्ता कांग्रेस कार्यसमिति में 'वंदे मातरम' गान के विभाजन की अनुशंसा और कुछ नहीं बल्कि एक 'इमोशनल राष्ट्रीय ब्लैक मेल' था। यह देश विभाजन में अपना हित देखने वाले नेताओं द्वारा निर्मित 'ब्लैकमेल' था। आदरणीय बंकिम बाबू ने जब भारतमाता को केवल एक भौगोलिक भू–भाग के रूप में नहीं, बल्कि साक्षात् देवी और जननी के रूप में देखा, तो उनके मानस में श्सोनार बांग्लाश और संपूर्ण भारतवर्ष का एक ऐसा दिव्य चित्र उभर आया, जिसने औपनिवेशिक दास्तां के अंधकार को चीरकर रख दिया। विडंबना, वंचना, विसंगति, विचित्र, यह है कि जिस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, क्रांतिकारियों और हुतात्माओं को हँसते–हँसते फाँसी के फंदों को जयमाल मान लेने की असीम शक्ति दी, उसी महान कृति को स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति और तुष्टिकरण के बवंडर में उलझा दिया गया। मुस्लिम तुष्टिकरण के मकड़जाल ने वंदेमातरम् को कोई एक सौ वर्षों तक, उसके पूर्ण गान से वंचित रखा। प्रश्न यह है कि यदि प्रथम दो छंद पहले से ही कई कांग्रेस सभाओं में प्रचलित थे, तो 1937 में उसे औपचारिक रूप से सीमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्तुतः कांग्रेस, मुस्लिम तुष्टिकरण का समायोजन कर रही थी।

काले धन और अवैध सौदों का चक्र टूटेगा

रजनीश कपूर

समाज को चाहिए कि वह अपने आदर्श माने जाने वाली हस्तियों से उच्च नैतिक मानदंडों की अपेक्षा करे। फिर वो चाहे कोई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हो, आध्यात्मिक गुरु हो, उद्योगपति हो, या कोई अन्य मशहूर हस्ती, जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अदालतों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। आए दिन हमें यह देखने को मिलता है कि उद्योग जगत, मनोरंजन जगत, आध्यात्मिक संस्थाओं और खेल जगत के कुछ नामी–गिरामी हस्तियों के नाम बार–बार श्मनी लॉन्ड्रिंगच्च, फर्जी सौदों और संदिग्ध वित्तीय लेन–देन के मामलों में चर्चा में आते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में अपनी मेहनत, प्रतिभा और लोकप्रियता से करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता है। फिर भी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अच्छी छवि को दाव पर लगाकर काले धन के सौदों में उलझ जाते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल उनके व्यक्तिगत पतन का संकेत है, बल्कि पूरे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ों को और मजबूत करती है। गौरतलब है कि इन हस्तियों के पास पहले से ही करोड़ों की अपार संपत्ति, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्मों या मैचों से की गई कमाई और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। फिर भी वे अवैध गतिविधियों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? एक बड़ा कारण है लोभ। सफलता के बाद भी और अधिक धन और अधिक पावर की भूख कभी नहीं मिटती। कई बार वे सोचते हैं कि उनकी छवि इतनी मजबूत है कि कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। कुछ लोग अपने व्यवसाय को श्विविधीकरणच्च का नाम देकर रियल एस्टेट, शेल कंपनियों, दान के नाम पर काले धन को सफेद करना या विदेशी खातों के जरिए धन छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बनाई हुई प्रतिष्ठा एक सुरक्षा कवच लगती है, लेकिन असल में यह उनके गिरने का कारण बन जाती है। कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि ये लोग अपने सरकारी संपर्कों और प्रभावशाली लोगों से परिचित होने के कारण अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी या मामला दबा दिया जाएगा। यह आत्मविश्वास अक्सर गलत साबित होता है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो। फिर भी व्यवहार में कई बार प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच धीमी पड़ जाती है या सबूतों की कमी का हवाला देकर मामले कमजोर हो जाते हैं। भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां जब ऐसे मामलों की जांच करती हैं, तो अक्सर आरोपियों को सजा नहीं दिला पाती। इसके कई कारण हो सकते हैंय जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, सबूतों की कमी, गवाहों का दबाव में आना या लंबी अदालती सुनवाई। कभी–कभी राजनीतिक प्रभाव या संसाधनों की कमी भी जांच को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसे श्जाहिर कारणोंच्च से बरी होना या मामला रुक जाना समाज में गलत संदेश देता है। आम आदमी सोचता है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है। यह श्गरीब लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस स्थिति में अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई करे, सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और दोषियों को उचित सजा दे। विशेष अदालतें या फास्ट–ट्रैक प्रक्रियाएं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों के लिए बनाई जा सकती हैं। अदालतें एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दे सकती हैं कि जांच में देरी न की जाए और कोई भी प्रभाव जांच को बाधित न करे। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय तभी प्रभावी होगा जब वह बिना भेदभाव के लागू हो। जरूरत है तो इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना की। जनता को समझना चाहिए कि सेलेब्रिटीज की चमकदार जिंदगी के पीछे कई बार काले कारोबार की छाया होती है। मीडिया और जागरूक नागरिकों को ऐसे मामलों की लगातार निगरानी करनी चाहिए। एजेंसियों को चाहिए कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। शिकायत दर्ज होने के बाद प्रारंभिक जांच तुरंत शुरू होनी चाहिए और सबूतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि शिकायत में गंभीर आरोप हों और उसके ठोस प्रमाण भी संलग्न हों तो जांच एजेंसियों जिम्मेदारी हो कि शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाए। कानून के जानकार मानते हैं कि शिकायत दर्ज कराने के लिए ठोस सबूत जरूरी होते हैं। सामान्य दस्तावेजी सबूतों में बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी दस्तावेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर्स, इनकम टैक्स रिटर्न और संदिग्ध लेन–देन के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। डिजिटल सबूत आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हैंय ऑडी–वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप के चौट, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल वॉलेट के लेन–देन, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन, क्लाउड स्टोरेज में सेव की गई फाइलें और सर्वर लॉग। ये सबूत समय–स्टैम्प के साथ उपलब्ध होने चाहिए और श्चेन ऑफ कस्टडीच्च बनाए रखते हुए पेश किए जाने चाहिए। इसके साथ ही गवाहों के बयान और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी मजबूत आधार प्रदान करते हैं। शिकायतकर्ता को चाहिए कि वह सभी उपलब्ध जानकारी व्यवस्थित रूप से एजेंसी को सौंपे और जांच में सहयोग करे। समाज को चाहिए कि वह अपने आदर्श माने जाने वाली हस्तियों से उच्च नैतिक मानदंडों की अपेक्षा करे। फिर वो चाहे कोई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हो, आध्यात्मिक गुरु हो, उद्योगपति हो, या कोई अन्य मशहूर हस्ती, जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अदालतों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। तभी हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकेंगे जहां प्रतिष्ठा और धन किसी को कानून से ऊपर न रख सकें। काले धन और अवैध सौदों का चक्र तभी टूटेगा जब हर नागरिक, हर संस्था और हर अदालत अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए।

27 अगस्त को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में होगा 'खेलो इंडिया संवाद', प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल संबोधन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त 2026 को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में 'खेलो इंडिया संवादकृ खेल की बात, पीएम के साथ' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और मेरा युवा भारत जौनपुर के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के दिशा–निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन से होगी। इसका देशभर के जनपदों में एक साथ लाइव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का स्वागत संबोधन तथा राष्ट्रीय खेल दिवस पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने बताया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर तथा राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर को कैटेगरी–ए के लिए चयनित किया गया है। यहां लाइव प्रसारण के साथ दो–तरफा संवाद की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं सल्तनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर और महात्मा गांधी शती स्मारक महाविद्यालय, गरुआ, मकसूदपुर, गाजीपुर को कैटेगरी–बी में चयनित किया गया है। यहां लाइव प्रसारण के साथ एक–तरफा संवाद की व्यवस्था होगी। युवा अधिकारी तन्मय मोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय खिलाड़ियों के साथ मॉडरेटेड परिचर्चा, जनप्रतिनिधियों का संबोधन और युवाओं के विचार एवं आकांक्षाओं को जानने के लिए 15 मिनट का 'युवा संवाद' सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान युवा चार प्रमुख विषयों पर अपने सुझाव रखेंगे। इनमें देश में खेल पारितंत्र को मजबूत बनाना, 2036 ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं का विकास, शासन–व्यवस्था में युवा नेतृत्व एवं सहभागिता तथा विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना शामिल है। कार्यक्रम में युवाओं को 'मेरा भारत' पोर्टल पर पंजीकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों एवं मेरा युवा भारत के जिला संयोजकों ने जिले के छात्र–छात्राओं और युवाओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील की है।

बोलेरो की टक्कर से बुलेट सवार दंपती की मौत, पत्नी ने मौके पर तोड़ा दमय पति की अस्पताल में मौत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बदलापुर थाना क्षेत्र के कालिंजरा मोड़ के पास रविवार देर शाम को तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से बुलेट सवार दंपती की मौत हो गई। हादसे में पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी रमेश गौतम (29) अपनी पत्नी रीता देवी (35) के साथ रविवार को बुलेट से जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव जा रहे थे। बताया गया कि शाहपुर में उनकी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई थी। दोनों शोक संवेदना व्यक्त करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में बदलापुर थाना क्षेत्र के कालिंजरा मोड़ के पास उनकी बुलेट सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में रीता देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रमेश गौतम को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम दंपती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि मृतक दंपती के दो पुत्र हैं। माता–पिता की मौत से बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का रो–रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई सूचना पर पहुंची बदलापुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में शामिल बोलेरो के संबंध में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बदलापुर थानाध्यक्ष फूलचंद्र पांडेय ने रविवार शाम करीब सात बजे बताया कि सड़क हादसे में दंपती की मौत हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, कांग्रेस ने एफआईआर के लिए सौंपा पत्रक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जौनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्नाव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के बीच विधानसभा अध्यक्ष मंच से चले गए। इसे पार्टी ने राष्ट्रगान

का अपमान बताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह और शहर अध्यक्ष आरिफ खान के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनीता सिंह को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें सतीश महाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगान के अपमान का आरोप गंभीर है। उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शहर अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि राष्ट्रगान देश की गरिमा और सम्मान का प्रतीक है। इसके अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। खबर लिखे जाने तक प्रार्थना पत्र के आधार पर जौनपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा, लाल प्रकाश पाल, सभासद शहनवाज मंजूर, देवराज पांडेय, फैयाज हाशमी, इरशाद खान, कृष्णचंद निषाद, अरविंद यादव, चंद्रभान सिंह, वैश खान, इस्तेखारुल प्रधान, मुहम्मद ताहिर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसकेडी हॉस्पिटल ने 22 अगस्त को 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट का शुभारंभ किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसकेडी ग्रुप की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा इकाई एसकेडी हॉस्पिटल ने 22 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपने 17 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी की। वर्ष 2009 में स्थापना के बाद से ही एसकेडी हॉस्पिटल समुदाय को नैतिक, किफायती एवं आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप अस्पताल ने लगातार अपनी चिकित्सा सुविधाओं, तकनीक एवं चिकित्सकीय विशेषज्ञता को उन्नत किया है। इस अवसर पर एसकेडी हॉस्पिटल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अत्याधुनिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट का शुभारंभ किया। यह यूनिट ऑर्थोपेडिक उपचार में सटीकता और आधुनिक तकनीक के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यूनिट का उद्घाटन सरोजिनी नगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया। रोबोटिक–सहायता प्राप्त जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक के माध्यम से एसकेडी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी में अधिक सटीकता, व्यक्तिगत सर्जिकल प्लानिंग, छोटे चीरे, इम्प्लांट की बेहतर पोजिशनिंग, कम रक्तस्राव, तेजी से रिकवरी, कम पोस्ट–ऑपरेटिव दर्द, बेहतर गतिशीलता तथा लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

इस अवसर पर एसकेडी हॉस्पिटल के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. आशीष सिंह ने कहा

"पिछले 17 वर्षों में एसकेडी हॉस्पिटल लगातार एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा हैकृअपने मरीजों को करुणा और उत्कृष्टता के साथ विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत हमारे मरीजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हम बेहतर मरीज परिणामों के लिए नवीनतम चिकित्सा तकनीकों को अपनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।"

एसकेडी हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर तृप्ति सिंह ने कहारू

"स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और एसकेडी हॉस्पिटल नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रोबोटिक सर्जरी प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक तकनीक को गुणवत्तापूर्ण मरीज देखभाल के साथ जोड़ने की हमारी सोच को दर्शाता है। पिछले 17 वर्षों में मरीजों और समुदाय द्वारा हम पर जताए गए विश्वास के लिए हम हृदय से आभारी हैं।"

इस अवसर पर एसकेडी ग्रुप के चेयरमैन एस.के.डी. सिंह एवं एसकेडी एकेडमी के डायरेक्टर मनीष सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके नेतृत्व ने एसकेडी हॉस्पिटल के निरंतर विस्तार एवं आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एसकेडी हॉस्पिटल में उपलब्ध प्रमुख सेवाएं

रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी

जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं आथ्रीस्कोपी

एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक्स एवं ट्रॉमा केयर

पूर्ण रूप से सुसज्जित कैथ लैब के साथ कार्डियोलॉजी सेवाएं

कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एवं पेसमेकर इम्प्लांटेशन

प्रसूति एवं स्त्री रोग सेवाएं

एडवांस्ड गायनेकोलॉजिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी

आईवीएफ एवं इन्फर्टिलिटी सेवाएं

क्रिटिकल केयर एवं आईसीयू एनआईसीयू

डायलिसिस सेवाएं

चेस्ट एवं ट्यूबरकुलोसिस केयर

न्यूरोलॉजी

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी

जनरल मेडिसिन

जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी

व्यापक डायग्नोस्टिक एवं इमरजेंसी सेवाएं

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के अपने विजन के तहत एसकेडी ग्रुप लखनऊ के वृंदावन योजना में एक नए अत्याधुनिक एसकेडी हॉस्पिटल कैंपस का भी निर्माण कर रहा है। यह कैंपस नवीनतम चिकित्सा तकनीक एवं मरीज–केंद्रित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्नत सुपर–स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

17 वर्षों के विश्वास, नवाचार एवं चिकित्सकीय उत्कृष्टता के साथ एसकेडी हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्नत, सुलभ एवं संवेदनशील चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, रंग–बिरंगी राखियों से सजी दुकानें

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भाई–बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को लेकर जौनपुर के बाजारों में चहल–पहल बढ़ गई है। शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राखियों की दुकानें रंग–बिरंगी और आकर्षक राखियों से सज गई हैं। पर्व को लेकर दुकानदारों ने विभिन्न डिजाइन और कीमतों की राखियों का पर्याप्त स्टॉक किया है। बाजार में हर वर्ग और बजट के अनुरूप राखियां उपलब्ध हैं। दुकानदार रमेश ने बताया कि मौली, रेशम और बड्स से बनी पारंपरिक राखियों के साथ मोती, स्टोन और फैंसी डिजाइन वाली राखियों की भी खूब मांग है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटा भीम, स्पाइडरमैन और विभिन्न सुपरहीरो थीम वाली राखियां दुकानों पर विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में भाभियों को रक्षा सूत्र बांधने का चलन भी बढ़ा है। इसे देखते हुए दुकानदारों ने गुजरात और कोलकाता से आकर्षक 'लुंबा' सेट मंगाए हैं। इनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक है। महिलाओं में इन लुंबा सेट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राखियों के साथ पूजन सामग्री की बिक्री में भी तेजी आई है। पूजा की सजावटी थाली, रोली, चंदन, अक्षत और मौली की मांग बढ़ गई है। ओलंदगंज के व्यापारी सौरभ सेठ और आदर्श गुप्ता ने बताया कि ग्राहक सुबह से ही राखी और अन्य सामान की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानों पर गिफ्ट आइटम और सजावटी सामान भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। सुजानगंज समेत जिले के अन्य ग्रामीण बाजारों में भी राखी की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों को रक्षाबंधन के नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा एम पी मैरिज लॉन निकट बाबा मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल राजीव पंत , सेना मेडल, विशिष्ट अध्यक्ष श्री संजीव खरे जी विभाग बौद्धिक प्रमुख उन्नाव विभाग, एवं प्रांत अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बीरेंद्र सिंह तोमर व पूर्व विधायक श्री गंगा सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, भा ज पा महिला जिला अध्यक्ष श्री मती अलका गुप्ता जी, अंशुमान सिंह, अशोक सिंह आदि सभी अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, सुबेदार मेजर बी एल वर्मा ने मंच संचालन करते हुए वन्देमातरम गीत एवं संगठन गीत से कार्यक्रम को शुरू कराया, अवध प्रांत के सभी 12 जिले लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती

एवं शाहजहांपुर समेत अवधप्रांत के सभी पदाधिकारी एवं मातृ शक्ति ने वार्षिक प्रतिनिधि सभा में भाग लिया, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष ने अपना वृत्त सुनाया, प्रांत की कार्यकारिणी की घोषणा प्रांत अध्यक्ष श्री तोमर जी ने की, हरदोई जिले से पूर्व विधायक विधायक श्री गंगा सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, अशोक सिंह, एवं अंशुमान सिंह, एवं हरदोई जिले के जिला अध्यक्ष अवशेष कुमार सिंह एवं प्रांत सचिव राहुल सिंह फौजी ने सैनिक जीवन, संगठन परिचय, विस्तार, कैप्टन सरोज सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कविता सुनाकर सभी में जोस भर दिया, शहीद की पत्नी एवं उनके परिवार को अंगवस्त्र एवं नरसिंह भगवान की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया, समस्त प्रोग्राम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरदोई टीम द्वारा आयोजित किया गया, राष्ट्रगान के बाद बैठक को सम्पन्न किया गया।

अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट ने मनाई हरियाली तीज, महिलाओं ने की शिव–पार्वती की पूजा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। हरियाली तीज के अवसर पर अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट परिवार की ओर से सोमवार को शहर के एक लॉन में तीज उत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव–पार्वती और गणेश जी की पूजा–अर्चना से हुई। मुख्य अतिथियों डॉ. शकुंतला यादव, डॉ. स्वाति यादव, डॉ. शैली निगम, रीता जायसवाल, बबीता सिंह, पायल किन्नर और राधिका सिंह ने पूजन किया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने हरे रंग के परिधान धारण कर पारंपरिक तरीके से हरियाली तीज मनाई। महिलाओं ने भगवान शिव के भक्ति गीत गाकर अपने पतियों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में कजरी और भक्ति गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। ट्रस्ट की ओर से महिलाओं को पान खिलाकर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। किन्नर समिति के सदस्यों ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका सभी ने आनंद लिया। महिलाओं ने भी उत्साह के साथ नृत्य में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ट्रस्ट परिवार की ओर से कार्यक्रम में शामिल सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री भेंट की गई। इसमें सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां और अन्य श्रृंगार सामग्री शामिल रही। कार्यक्रम में डॉ. शुभा सिंह, डॉ. श्वेता सिंह, डॉ. माया सिंह, डॉ. अलकेश्वरी सिंह, डॉ. ममता दूबे, वंदना सरकार, डॉ. अंजना श्रीवास्तव, मीरा अग्रहरि, नीलम मिश्रा, सरोज गुप्ता, क्षमा सिंह, पूनम सिंह, रेखा सिंह, राखी सिंह, किरण सिंह, अंजू सिंह, गीता दूबे, नेहा सिंह, रिचा सिंह, अर्चना सिंह, प्रीति गुप्ता, रजनी साहू, सरिता सिंह, रेखा मिश्रा, रेनू गुप्ता, सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। किन्नर समाज के भी कई सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए।

ज्ञान प्रसार संस्थान का 23वाँ वार्षिक समारोह – समाजसेवा के 24 वर्ष

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।ज्ञान प्रसार संस्थान का 23वाँ वार्षिक समारोह श्री जी.बी. सिंह फाउंडेशन, विवेक खंड में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री मृत्युंजय प्रसाद गुप्त, संपादक, विश्व विधायक एवं संसद से सड़क तक, ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए संस्थान के शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों की सराहना की। अध्यक्ष श्रीमती नीरजा द्विवेदी ने बताया कि 2003 में 15दृ20 वंचित बच्चों से प्रारम्भ संस्थान आज प्रतिदिन 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है और अब तक हजारों बच्चे लाभान्वित हुए हैं। आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन से विद्यार्थियों ने एलएल.बी., एम.कॉम., पॉलिटेक्निक, फिजियोथेरेपी, बी.एड., बी.ए., बी.कॉम. सहित उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहीं अन्य बच्चों ने विभिन्न आजीविका कौशल सीखकर आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति की। उन्होंने श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती प्रियम्बदा देवी मिश्रा, परिवार एवं शिक्षकों के योगदान को स्मरण किया। समारोह में अक्षत मौर्य, नेहा, निशा, सबा एवं कहकशाँ की प्रस्तुतियाँ विशेष आकर्षण रहीं। श्री जी.बी. सिंह फाउंडेशन ने आयोजन एवं समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग दिया। वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्रदीप सिंह ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं वरिष्ठ शिक्षकों को पौधों एवं ट्रॉफियों तथा 50 उत्कृष्ट बच्चों को प्रमाण–पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन में श्री एम.सी. द्विवेदी, आईपीएस, डीजीपी (सेवानिवृत्त) ने फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती मीना सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए वर्ष 2022 से स्वर्गीय श्री जी.बी. सिंह जी की प्रेरणा से शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण के साथ राष्ट्रभावना, नैतिक मूल्यों एवं लोकसेवा को समर्पित कार्यों की सराहना की। श्री जी.बी. सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गोकर्ण सिंह,ब्रजेश्वरी जायसवाल, सुमन जायसवाल, संजय निगम, पी के सिंह, टी पी भंडारी,श्रीनिवास पांडे, अवध नरेश तिवारी, सोनू सिंह यादव, जयनारायण सिंह चौहान, शिवम गुप्ता,अंशुमान त्रिपाठी,रोहित त्रिपाठी शहीद सम्मानित नागरिकों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

विश्वकर्मा अल्युमिनियम वर्क्स का भव्य उदघाटन संपन्न, पूजा–अर्चना व सुंदरकांड के साथ हुआ शुभारंभ

देश की उपासना समाचार पत्र

मुम्बई ब्यूरो चीफ धनन्जय विश्वकर्मा

मुम्बई/वसई। वसई–विरार महानगरपालिका क्षेत्र में रेंज ऑफिस के पास एचडीएफसी बैंक के सामने विश्वकर्मा अल्युमिनियम वर्क्स का भव्य उदघाटन धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी एवं विश्वकर्मा संस्था वसई के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा (राजू भाई) ने परिवार, मित्रों एवं समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा–अर्चना एवं आरती के साथ हुई। इसके बाद रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने सहभागिता की। शाम तक भजन–कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रतिष्ठान के संचालक राजेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें अल्युमिनियम एवं फर्नीचर के क्षेत्र में करीब 25 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अल्युमिनियम, ग्लास, फर्नीचर एवं संबंधित कार्यों में बेहतर गुणवत्ता, उचित मूल्य और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का उनका प्रयास रहेगा। समारोह के दौरान एकार्थी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर विश्वकर्मा संस्था वसई के उपाध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, अखिलेश विश्वकर्मा, रविन्द्र विश्वकर्मा, अरविन्द विश्वकर्मा, एकार्थी फाउंडेशन नायगांव के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष बच्चन विश्वकर्मा, पत्रकार धनंजय विश्वकर्मा सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे। प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर उपस्थित लोगों ने संचालक राजेंद्र विश्वकर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं व्यवसाय की सफलता की शुभकामनाएं दीं।

'बारावफात व रक्षाबंधन पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर पीस कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' सोमवार को रबीउल अव्वल(बारावफात) और रक्षाबंधन के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण से मनाने के लिए पाली थाना परिसर में सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राजनारायण एवं उपजिलाधिकारी सवायजपुर शिवानी सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत लोगों ने भाग लिया। एएसपी आलोक राजनारायण एवं एसडीएम शिवानी सिंह ने त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम शिवानी सिंह ने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाये रखें।साथ ही किसी अपवाह पर ध्यान न दें। वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राजनारायण ने कहा कि शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने लोगों से अपील की कहा कि बारावफात के दौरान प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस दें। बैठक में थाना प्रभारी विजय कुमार मिश्रा, कस्बा इंचार्ज अचल कुमार सहित पुलिस कर्मी व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

खाद्य विभाग की शिथिलता के चलते रक्षाबंधन से पूर्व सक्रिय हुए मिलावट खोर

अयोध्या।रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मिठाई, खोवा, पनीर, छेना और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी है।त्योहार की बढ़ती खपत को देखते हुए मिलावटखोरों के सक्रिय होने की आशंका भी बढ़ गई है।आरोप है कि अधिक मुनाफे के लालच में कुछ प्रतिष्ठान संचालक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने से भी पीछे नहीं हटते।ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। रक्षाबंधन पर काफी मात्रा में मिठाइयों, खोवा, पनीर, छेना और दूध से बने उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावट की आशंका रहती है। हर साल दीपावली, होली, रक्षाबंधन समेत प्रमुख त्योहारों के दौरान खाद्य विभाग द्वारा भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां पनीर खोवे आज बरामद किए जाते हैं और नष्ट भी किए जाते हैं परंतु रक्षाबंधन पर्व एक सप्ताह से भी कम रह गया है।लेकिन खाद्य विभाग इन मिलावट करने वाले लोगो पर अंकुश लगाने में असफल दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि जब कोई त्यौहार खास कर होली दीपावली रक्षाबंधन या अन्य पर्व ऐसे आते हैं जब मिठाइयां व दूध से निर्मित अन्य खाद्य पदार्थों की खपत भारी मात्रा में होती है तभी कुछ दिन पहले खाद्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जागकर कुछ ही छोटे–मोटे प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाकर खाना पूर्ति कर लेता है। लोगों का यह भी मानना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग सिर्फ रक्षाबंधन सहित अन्य प्रभु से पहले ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी चेकिंग अभियान चलाए लेकिन ऐसा नहीं होता है।कहनाशहर के साथ–साथ ग्रामीण बाजारों, मिठाई की दुकानों, डेयरी प्रतिष्ठानों और खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले केंद्रों पर औचक जांच शुरू करे। खोवा, पनीर, दूध, छेना और मिठाइयों के नमूने लेकर उनकी जांच कराई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।लोगों का कहना है कि कार्रवाई किसी घटना के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले होनी चाहिए। यदि समय रहते अभियान चलाकर मिलावट पर अंकुश लगाया जाए तो रक्षाबंधन पर बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोका जा सकता है। अब देखना यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग रक्षाबंधन से पहले सक्रिय होकर व्यापक अभियान चलाता है या फिर त्योहार बीतने के बाद औपचारिक कार्रवाई तक ही मामला सीमित रह जाता है।सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि आज सोमवार से मिलावट करने वाले मिलावट खोर पर अंकुश लगाने के लिए दो टीम का गठन किया गया है।

गहनाग मेला सकुशल सम्पन्न ,तीन लाख लोग हुये शामिल

अयोध्या। जिले के अमानीगंज विकास खण्ड के गहनाग गांव में स्थित प्रसिद्ध नागपीठ गहनाग का बडा मेला शांतिपूर्वक ढंग से सकुशल सम्पन्न हो गया।नागपंचमी के बाद पडने वाले सोमवार को लगने वाले इस मेले में प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया हजारों की संख्या में बडे वाहनों से दूर दूर से आये लोग लाइन में लगकर दर्शन पूजन कर रहे थे बिभिन्न जनपदों से आये दुकानदार दो दिन पहले ही पहुंच चुके थे मेले में लकडी और लोहे के सामनों की बिक्री ज्यादा रही।मेले में स्वयं सेवी संस्थाओं निरंकारी मिशन रूदौली, डा बंगाली रामनगर, आदि के तरफ से सेवा व जलपान कैम्प लगाया गया।मेले में प्रशासन ने तीन लाख से अधिक लोगों के आने का दावा कियाने थाना प्रभारी खण्डासा के प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार सोनकर ने बताया कि लगभग तीन लाख लोगों के आने का अनुमान है।गहनाग मेले की सुरक्षा व्यवस्था में बडे पैमाने पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया था इसके साथ डेढ कम्पनी पीएसी अग्नि समन दस्ता दो दर्जन महिला उप निरीक्षक शदिन भर लगातार लगे रहे आठ स्थानों पर बैरियर लगाकर रूट चेन्ज किया गया था खोया पाया कैम्प मे दर्जनों बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया।पुलिस के मुताबिक 18 स्थानों पर प्वाइंट बना कर पुलिस को तैनात किया गया था मेले के सकुशल निपटने पर प्रशासन ने राहत की सांश ली इस मेले में पास पडोस के जिलों से भारी भीड़ जमा हो जाती है।

पीएम पोषण योजना के रसोइयों का सम्मान, कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को कलेक्ट्रेट के प्रेक्षागृह में किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्या, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन और मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया समेत अधिकारी व रसोइया मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की थीम 'स्वस्थ बच्चे, खिलता बचपनकृ सही पोषण से प्रदेश रोशन' रही। इस मौके पर राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि पीएम पोषण योजना के रसोइया विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वहीं वर्ष में एक बार साड़ी या ड्रेस के लिए मिलने वाली राशि 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में पीएम पोषण योजना के तहत कुल 8,325 रसोइया कार्यरत हैं। कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 15 रसोइयों को बढ़े हुए मानदेय का चेक और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्या ने कहा कि सरकार रसोइयों के हित में लगातार कार्य कर रही है। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने कहा कि शेष सभी रसोइयों का पंजीकरण एक माह के भीतर पूरा कर उन्हें कैशलेस चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौष्टिक भोजन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में तेजी आएगी। कार्यक्रम में संगीता सरोज, कुसुम, छोटेलाल यादव समेत 15 रसोइयों को प्रतीकात्मक रूप से कार्ड वितरित किए गए। रसोइयों ने सरकार के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में रसोइया मौजूद रहे।

जनसुनवाई के दौरान महिला एसओ तथा उनकी टीम मौके पर फरियादियों की समस्या की कर रही समाधान

अयोध्या। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेस 5 नोडल प्रभारी बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी की पर्यवेक्षण में प्रतिदिन महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला जहां एक ओर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को स्कूलों, चौराहा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर अपनी टीम के साथ जाकर महिलाओं बालिकाओं तथा छात्रों को जागरुक कर रही हैं।वहीं महिला थाना पर आने वाली दूर दराज से फरियादियों की समस्याओं का समाधान जनसुनवाई के दौरान अपनी सूझबूझ से भी कर रही हैं।जनसुनवाई के दौरान पति–पत्नी से मनमुटाव,छोटी–छोटी बातों में पति–पत्नी के बीच वाद विवाद उत्पन्न होना सहित कई जटिल समस्याओं का समाधान हुए कुछ ही समय में निपटारा कर रही है।उनके साथ–साथ इन फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने में महिला थाना पर तैनात महिला उप निरीक्षक सोनी, श्वेता राठौड़, प्रिया भी सहयोग करती हुई दिखाई दे रही थी।

छात्राओं ने एसपी ग्रामीण और सीओ सदर को बांधी राखी

अयोध्या। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सोमवार को पुलिस लाइन मे अवध इंटरनेशनल स्कूल एवं डीएन स्कूल, पूरा बाजार की छात्राओं ने पुलिस लाइन आकर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी और सीओ सदर प्रतीक कुमार की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।इस दौरान छात्राओं ने दोनों पुलिस अधिकारियों के माथे पर तिलक लगाकर आरती

उतारी।इसके बाद उनकी कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।राखी बंधवाने के बाद एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी और सीओ सदर प्रतीक कुमार ने छात्राओं को उपहार भेंट किए तथा उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

'बारावफात व रक्षाबंधन पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर पीस कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'पाली–(हरदोई)' सोमवार को रबीउल अव्वल(बारावफात) और रक्षाबंधन के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण से मनाने के लिए पाली थाना परिसर में सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक

राजनारायण एवं उपजिलाधिकारी सवायजपुर शिवानी सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से पीस कमेटी की बैठक ध

नगर निगम को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, जल प्रबंधन के नवाचार में मिला सम्मान

गोरखपुर, (संवाददाता)। शहरी जल प्रबंधन में तकनीक, प्रकृति आधारित समाधान और जनभागीदारी के जरिये किए गए प्रयासों के लिए गोरखपुर नगर निगम को प्रतिष्ठित जीईईएफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2026 के तहत इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मेयर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने सम्मान ग्रहण किया। सम्मेलन का विषय आने वाली पीढ़ियों के लिए जलस्रोत से सतत विकास तक नवाचार को बढ़ावा देना रहा। सम्मान ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया। मेयर ने सम्मेलन में बताया कि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थापित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के तहत 110 स्वचालित जलस्तर सेंसर, वर्षा पूर्वानुमान प्रणाली, जलनिकासी नेटवर्क का डिजिटल ट्विन, वास्तविक समय निगरानी और स्वचालित पंपिंग व्यवस्था को एकीकृत किया गया है। शहर के 25 प्रमुख पंपिंग स्टेशनों में से 21 को स्काडा आधारित स्वचालन से जोड़ा जा चुका है। महापौर के अनुसार वर्ष 2025 के मानसून में इन व्यवस्थाओं के चलते जलभराव की औसत अवधि 12 घंटे से घटकर डेढ़ घंटे से भी कम रह गई। इसके अलावा तकियाघाट में वेटलैंड, रॉक फिल्टर और स्थानीय वनस्पतियों के जरिये अपशिष्ट जल उपचार किया गया। मोती पोखरा में नैनो बबल और अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड समिट 2026 में मेयर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने स्मार्ट और सतत जल प्रबंधन वास्तविक प्रभाव देने वाली तकनीकों का विस्तार विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने गोरखपुर में जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे तकनीक आधारित प्रयासों और उनके प्रभाव के बारे में अनुभव साझा किया।

छत पर मिला युवक का खून से लथपथ शव, सिर पर चोट के निशान– परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। खोराबार थाना क्षेत्र के सिक्टौर में शनिवार सुबह 35 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव छत पर मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर एसपी सिटी निमिष पाटील समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी है। मृतक की पहचान सिक्टौर निवासी प्रदीप पासवान के रूप में हुई है। शनिवार सुबह पड़ोसियों की नजर छत पर पड़े उसके शव पर पड़ी। शव खून से लथपथ था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजन के अनुसार, प्रदीप करीब एक माह पहले ही बाहर नौकरी करने के बाद घर लौटा था। इन दिनों वह अपने घर के पास चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था। प्रदीप की पारिवारिक स्थिति भी काफी परेशानियों भरी थी। करीब पांच साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसके दो बच्चे हैं, जिनमें 10 वर्षीय बेटा और छह वर्षीय बेटी शामिल हैं। युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव और घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सिर पर लगी चोट और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हरियांव में तीन अवैध प्लाटिंग पर चला बीडा का बुलडोजर

वाराणसी, (संवाददाता)। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीडा क्षेत्र मे अवैध रूप से हो रहे प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई कर अवैध रूप से बसाने वाली कालोनी को ध्वस्त कर दिया। एक ही दिन कुल तीन कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जिलाधिकारी व बीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर उप कार्यपालक अधिकारी निखिल यादव के नेतृत्व में हुई है। इस मौके पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल भी मौजूद रही। बीडा के उप कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि पहली कार्रवाई में 4 हजार वर्ग मीटर पर श्रीमती अनुराधा निवासी निवासी रजपुरा कालोनी, दूसरी कार्रवाई में ढाई हजार वर्ग मीटर पर अरुण कुमार सिंह निवासी हरियांव द्वारा विकसित की जा रही कालोनी तथा तीसरी कार्रवाई में पांच हजार वर्ग मीटर पर अरुण कुमार सिंह निवासी हरियांव द्वारा विकसित की जा रही अवैध भू–विन्यास (प्लाटिंग) पर कार्रवाई की गई है। बताया कि बीडा की ओर से अनाधिकृत रूप से बसाए जा रही कॉलोनियों तथा बिना मानचित्र स्वीकृति के कराए जा रहे निर्माण कार्य पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। बताया कि उक्त सभी भूखंड प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हरियावं में स्थित हैं।

एटीएम कार्ड बदलकर युवती के खाते से 40 हजार निकाले, प्राथमिकी दर्ज

गोरखपुर, (संवाददाता)। थाना क्षेत्र के सूबा बाजार स्थित एसबीआई एटीएम पर रुपये निकालने गई युवती का कार्ड बदलकर उसके खाते से 40 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की बहन की तहरीर पर खोराबार पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस एटीएम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। कैंट थाना क्षेत्र के आरकेपुरम कॉलोनी निवासी नागेश्वर तिवारी की बेटी प्रिया तिवारी ने पुलिस को बताया कि 12 अगस्त को उनकी छोटी बहन खुशी खोराबार के सूबा बाजार स्थित एसबीआई एटीएम से रुपये निकालने गई थी। वहां तीन अज्ञात लोग उसके पास पहुंचे। प्रिया के मुताबिक, एटीएम से रुपये नहीं निकलने पर खुशी वहां से चली आई।

नगर निगम में एमबी पर हस्ताक्षर पर विवाद, उपसभापति ने अभियंताओं पर लगाए आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। नगर निगम में निर्माण कार्यों की मेजरमेंट बुक एमबी पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम की उपसभापति पूनम सिंह ने निर्माण विभाग के अभियंताओं पर निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में जाकर विकास कार्यों की एमबी पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर आयुक्त अजय जैन को पत्र भेजकर ऐसे मामलों की जांच कराने और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। उपसभापति ने पत्र में कहा है कि नगर निगम के निर्माण विभाग में दो अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंता तैनात हैं। अभियंताओं को अलग–अलग वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आरोप है कि जिम्मेदारी वाले वार्डों से इतर दूसरे क्षेत्रों में भी अभियंता हस्तक्षेप कर वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों की एमबी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पूनम सिंह ने आरोप लगाया है कि दूसरे वार्डों में हस्तक्षेप कर एमबी पर हस्ताक्षर करने के पीछे धन उगाही की जा रही है। उन्होंने नगर आयुक्त से संबंधित अभियंताओं की ओर से दूसरे वार्डों में कराए गए एमबी सत्यापन और उसके आधार पर किए गए भुगतानों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जांच में नियमों के उल्लंघन या किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव को भी पत्र भेजा गया है। नगर निगम में चल रही चर्चा के अनुसार एमबी सत्यापन का यह मामला राम जानकीनगर नाला निर्माण से जुड़ा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस कार्य के भुगतान में एमबी के सत्यापन में गड़बड़ी की गई है।

घरेलू हिंसा केस में 3 दिन पहले हुआ था दाखिल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर जिला जेल में तीन दिन पहले दाखिल हुए 30 वर्षीय विचाराधीन बंदी समीर शेख की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पीपीगंज क्षेत्र के जसवल बाजार का रहने वाला था। घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े एक मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद उसे तीन दिन पहले न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था। जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय ने बताया कि समीर शेख को 19 अगस्त 2026 को जिला जेल में दाखिल किया गया था। वह पहले से क्रॉनिक अल्कोहलिक था और लीवर व किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित था। जेल प्रशासन के अनुसार, 21 अगस्त की शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे दौरा पड़ा। जेल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया। जेल प्रशासन के मुताबिक, इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर बनी रही और रात करीब 8रू30 बजे विशेषज्ञ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मृतक बंदी के परिजनों को दे दी गई है। जेल प्रशासन ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट नामित करने का अनुरोध किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।